मोटा कमीशन नहीं मिले तो क्यों कराएं काम

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) सड़क, पानी-बिजली जैसी आधारभूत जरूरतों की कमी से जनता जूझती रहे एफएमडीए या नगर निगम के मोटे पेट वाले अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो तब ही काम कराते हैं जब उनकी जेब में विकास कार्य का हिस्सा पहुंचने का जुगाड़ हो जाता है। नीलम-अजरौंदा पुल की मरम्मत भी कई महीनों तक टलती रही क्योंकि बजट काफी कम था। अब सौ मीटर पुल की मरम्मत का दो करोड़ रुपये का बजट बना तो ही काम शुरू कराया गया। यही कुछ बाटा रेलवे ओवर ब्रिज की मरम्मत में भी देखने को मिल सकता है।

बाटा आरओबी पर हार्डवेयर से हाइवे और हाइवे से हार्डवेयर की ओर के ट्रैक पर छोटे मोटे गड्ढे हैं, पिलर के छोर पर बियरिंगों के जोड़ों पर भी गड्ढे हो गए हैं। यदि इन गड्ढों की अभी मरम्मत और पैचिंग करा दी जाए तो पांच से आठ लाख रुपये खर्च होंगे और ट्रैफिक बिना रोके एक से दो रात में दोनों ओर के ट्रैक दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन इस तरह मरम्मत कराने से तो न तो मोटा कमीशन बनेगा और जनता को भी तकलीफ नहीं होगी।

यही वजह है कि एफएमडीए के निकम्मे और कमीशनखोरी में माहिर अधिकारी इस पुल की मरम्मत नहीं करा रहे है। जब तक इस पुल की हालत बड़खल और नीलम-अजरौंदा पुलों जैसी नहीं हो जाएगी तब तक इसे टूटते फूटते रहने दिया जाएगा। भले ही पिलर के जोड़ पर टूट रही सड़क में फंस कर वाहन खराब होते रहें और पुल पर वाहन खराब होने के कारण जाम लगता रहे, एफएमडीए के अधिकारी कोई काम नहीं कराएंगे। ऐसा नहीं है कि बाटा पुल की सड़क पर गड्ढे होने की जानकारी इन अधिकारियों को नहीं है, पीड़ित वाहन चालक और जागरूक नागरिक आए दिन पुल मरम्मत कराने की मांग प्रशासन से करते रहते हैं। मीडिया में भी बाटा पुल के गड्ढों के कारण लोगों को होने वाली परेशानी पर खबर आती रहती है लेकिन मजाल है कि अधिकारी इसका संज्ञान लेकर कुछ काम कराएं।

जब तक मरम्मत का बजट कई करोड़ न पहुंच जाए और टेंडर प्रक्रिया के नाम पर सत्ता में बैठे साहब के चहेते को काम सौंपने की जमीन नहीं बने मरम्मत नहीं कराई जाती। एफएमडीए में भर्ती किए गए सेवानिवृत्त और नकारा अधिकारी भी अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने सत्ताधारी आकाओं को ही खुश कर कमीशन की मलाई खा रहे हैं। यही कारण है कि बाटा आरओबी की मरम्मत नहीं कराई जा रही। जब इसके गड्ढे इतने बड़े हो जाएंगे कि वाहनों का चलना दूभर हो जाए और खराब सड़क के कारण लंबा जाम लगने लगे, जाम के कारण आम जनता और वाहन चालक परेशान होने लगें तब इसकी मरम्मत के बारे में सोचा जाएगा।

एक कमेटी जांच करके मरम्मत पर करोड़ों रुपये और दो से तीन महीने पुल बंद रहने की रिपोर्ट तैयार करेगी। ठेकेदार, कमीशन आदि तय होने के बाद काम शुरू कराया जाएगा। क्योंकि ठेकेदार साहब का खास होता है और अपनी सुविधा के अनुसार काम करता है, तो मरम्मत के लिए तय समय सीमा से दोगुना ढाईगुना या तीन गुना समय लेकर भी उसे पूरा न कराए। बड़खल पुल की मरम्मत का उदाहरण सामने है। ठेकेदार ने पुल की कारपेटिंग तो कर दी लेकिन फुटपाथ और रेलिंग का काम अधूरा छोड़ दिया। एफएमडीए के 'होनहार' अधिकारियों ने दो तीन महीने बाद तक फुटपाथ और रेलिंग की मरम्मत करवाई।

इस बीच आम जनता धक्के खाएगी, पुल बंद होने के कारण हार्डवेयर चौक आने-जाने के लिए नीलम अजरौंदा का चक्कर काटेगी, सोहना पुल का रास्ता चुनना तो और घाटे का सौदा होगा क्योंकि इस पुल की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है और यहां दिन भर जाम की स्थिति ही रहती है।

जनता परेशान हो, उसका ईंधन और समय बर्बाद हो एफएमडीए के निकम्मे अधिकारियों को इससे कोई सरोकार नहीं, वो तो तभी काम करवाएंगे जब उनको कमाई करवाने वाले आका चाहेंगे।

'वमानी ओवरसीज' के...

पेज दो का शेष्ज्ञ

बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी अपेक्षा की कि मज़दूरों को भी अगले दिन अर्थात 21 अक्टूबर से ही काम पर आकर मन लगाकर काम में लग जाना चाहिए। मज़दूर तब से काम पर हैं, अपनी बात पर अटल हैं लेकिन मीटिंग से झल्लाए मालिकों ने अपने आश्वासनों को धता बताते हुए अगले दिन से ही मज़दूरों के मोबाइल ले जाने पर पाबन्दी लगा दी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। साथ ही लेट आने पर मज़दूरों को वापस लौटा दिया गया। इतना ही नहीं मज़दूर कार्यकर्ता दीपक यादव को 24 अक्टूबर को कंपनी के सीईओ सुशील कुमार सिंह, द्वारा धमकाया गया, 'मैं अभी-अभी लन्दन से आया हूं मुझे पता चला है कि तू बहुत बड़ा नेता बन रहा है। सुधर जा जैसे चल रहा है चलने दे वरना हमें समझाने के और भी तरीक़े आते हैं। और ये जो तेरा 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' है उससे दूर हट जा। उन्हें या तो हम भगा देंगे या ख़रीद लेंगे लेकिन तुम जितने भी क्रांतिकारी बने फिर रहे हो इन्हें एक-एक कर ठीक कराएंगे। हमसे पंगा मत लो, पछताओगे"। इस महाबली सीईओ को 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' के बारे में जानकारी मिली है उसने इसे बेचैन कर दिया है।

बिलकुल ऐसी ही घुड़की लखानी कंपनी के तथाकथित धाकड़ महाप्रबंधक से भी मिली थी। जब उसी भाषा में जवाब मिला और घटिया हरकतों से कोई फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आया तब लखानी ने मज़दूरों के साथ ही फ़रीदाबाद के श्रम, भविष्यनिधि, ईएसआई अधिकारीयों का भी सम्मान करना शुरू कर दिया 1.15 करोड़ रु का बैंक ड्राफ्ट अदब के साथ भविष्यनिधि विभाग में जमा किया और श्रम विभाग को आश्वस्त किया कि मज़दूरों की पाई-पाई चुकाऊंगा।

सभा के अंत में 'वमानी मजदूर संघर्ष समिति' की 25 सदस्यीय कोर कमेटी का चुनाव हुआ। जो इस तरह है; राजेश कुमार, सुनील, भैरो नाथ, देवेंद्र कुमार, बिंदेश्वरी उर्फ मुन्ना, सुनील कुमार, अजीत कुमार, केदार नाथ, अमर बहादुर, राजू कुमार, दीपक कुमार, छोटू, बिनोद, त्रिलोक, दीपू, नरेश, मंचला देवी, रिम्पी, सत्यवीर सिंह, नरेश कुमार, सोनू, राम पुकार, राम नरेश, अर्जुन सिंह और रिंकू। कोर कमेटी की पहली मीटिंग सभास्थल पर ही संपन्न हुई जिसमें 25 तारीख को पलवल श्रम कार्यालय में होने वाली मीटिंग में भाग लेने के लिए 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का चुनाव हुआ। जो इस तरह है; दीपक, केदारनाथ, विनोद, देवेन्द्र, नरेश, सत्यवीर, त्रिलोक तथा राजू।।

कंपनी की वेबसाइट में उपलब्ध कंपनी प्रोफाइल शानदार है: स्थापना 2008; 5 कारखाने, 6,000 से ज्यादा मज़दूर, हर महीने 14 लाख पौशाक बनाने की क्षमता, 5,000 सिलाई मशीन, 50 डिज़ाइनर, हर महीने 1,500 से ज्यादा डिज़ाइन, 50,000 से ज्यादा पक्के ग्राहक। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुशील कुमार सिंह, डायरेक्टर बलदेव राज भाटिया, राजकुमार भाटिया, विपेन कुमार भाटिया, मुकेश कुमार भाटिया, मीतेश भाटिया।

'मांग पत्र'

1) कई सालों से वेतन पुनर्निर्धारण समझौता नहीं हुआ है। कुशल तथा अर्ध कुशल श्रमिकों को भी अकुशल श्रमिकों का वेतन मिल रहा है। वार्षिक वेतन वृद्धि क़ानून का भी कोई अनुपालन नहीं हो रहा है। बेतहाशा बढ़ती मंहगाई के मद्देनज़र, द्विपक्षीय वार्ता द्वारा वेतन तथा सभी सम्बद्ध भत्तों आदि का पुनर्निर्धारण समझौता तत्काल किया जाए।

2) मज़दूरों को ओवर टाइम के लिए बाध्य किया जाता है। बंधुआ मज़दूरों की तरह देर रात तक ज़बरदस्ती काम कराया जाता है और उसका भुगतान डबल रेट से नहीं किया जाता। ये सरासर अन्याय ही नहीं बल्कि अपराध है। ओवरटाइम के लिए मज़दूरों से सहमति ली जाए तथा उसका भुगतान डबल रेट से हो।

3) बोनस का भुगतान कोई खैरात नहीं है। बोनस, मज़दूरों के वेतन के अनुरूप तथा कम से कम एक माह के वेतन के बराबर हो। बोनस का भुगतान शीघ्र किया जाए।

4) ड्यूटी का टाइम टेबल निश्चित हो, तथा इसे निश्चित जगह पर प्रदर्शित किया जाए।

5) ठेका श्रमिकों के नाम पर जिन मज़दूरों का शोषण हो रहा है उनके वेतन भत्ते आदि का भुगतान भी बाक़ी मज़दूरों के साथ ही किया जाए। इन मज़दूरों को भी नियमित किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'समान कार्य का समान वेतन' दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

6) देश के सभी श्रम क़ानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो। उन्हीं के अनुसार सभी छुट्टियां, मज़दूरों के छुट्टी खाते में जमा हों। हम बहुत दु:ख के साथ कह रहे हैं, कि आपके कार्यालय ने इस बाबत, स्वत: संज्ञान लेकर कोई क़दम नहीं उठाया।

7) कैंटीन की सुविधा बस नाम-चार की है। इससे सम्बंधित बहुत शिकायतें हैं। कई बार एक दिन का बचा हुआ, बासी खाना अगले दिन परोसा जाता है। खाने, नाश्ते, चाय आदि का मूल्य भी कैंटीन के अनुरूप न होकर, बाज़ार भाव जैसा ही है। दो बार चाय मिले तथा खाने व नाश्ते की गुणवत्ता सुधारी जाए तथा मेन्यू की रेट लिस्ट का पुनर्निर्धारण तत्काल किया जाए। श्रम संस्कृति का सम्मान करते हुए इस सम्बन्ध में मज़दूरों की राय ली जाए। शिकायत के लिए अधिकारी का नाम तथा मोबाइल नंबर कैंटीन में प्रदर्शित किया जाए। चाय अवकाश कम से कम 15 मिनट का रहे।

8) सभी मज़दूरों को कंपनी की ओर से सीजन के अनुसार,यूनिफ़ॉर्म तथा जूते उपलब्ध कराए जाएं।

9) मैनेजर, सुपरवाइजर, सुरक्षा गार्ड द्वारा, मज़दूरों के प्रति अपमानजनक बर्ताव तुरंत बंद हो।

कई सुपरवाइजरों को मज़दूरों से मुर्गा और बोतल ऐठने की गंदी लत लगी हुई है, प्रबंधन ऐसे सुपरवाइजर की आदतें तत्काल सुधार। किसी भी अपमानजनक बर्ताव को मज़दूर सहन नहीं करेंगे, ये बात नोट की जाए।

10) पलवल के लिए बस सुविधा उपलब्ध हो। ट्रेन से आने वाले मज़दूरों को गाड़ी लेट होने की स्थिति में, लेट आने की छूट हो और उन्हें ट्रेन के टाइम के अनुसार छोड़ा जाए।

11) हर महीने 2 गेट पास तथा 1 छुट्टी आवश्यक रूप से मिले।

12) दीवाली के अवसर पर, सभी मज़दूरों को सम्मानजनक उपहार तथा मिठाई का वितरण हो।

13) महिला कर्मचारियों की जांच पुरुष करते हैं। यह कार्यवाही अपराधपूर्ण है जिसे तुरंत बंद किया जाए। महिला गार्ड की नियुक्ति की जाए। जांच के नाम पर मज़दूरों के जूते उतरवाए जाना और उनके टिफिन को सूंघ कर देखना अपमानजनक है, ये प्रैक्टिस तत्काल बंद हो। महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिले तथा महिला सम्मान संवेदनशीलता कमेटी का गठन हो।

14) कार्य करते हुए अपंग हो जाने की स्थिति में अपंगता के अनुसार मुआवज़ा, आजीवन नौकरी तथा कार्य करते वक़्त या कंपनी आते-जाते वक़्त दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने पर रु. 50 लाख का मुआवज़ा और आश्रित को नौकरी सुनिश्चित किए जाएं।

15) रविवार के दिन डबल दर से वेतन के साथ ही सुपरवाइजर की तरह ही मज़दूरों को भी खाना मिले।

16) सैलरी एडवांस की रक़म निर्धारित हो तथा उसकी वसूली बिना किसी ब्याज के 12 महीने में किया जाए।

17) फैक्ट्री परिसर में, यूनियन दफ़्तर के लिए उचित जगह उपलब्ध कराई जाए।

18) फैक्ट्री में तत्काल मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक डॉक्टर पूरे दिन के लिए उपलब्ध कराया जाए।

19) मज़दूरों को कई बार बहुत आवश्यक काम से अपनी छुट्टी बढ़ानी पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में उन्हें फिर से अपरेंटिस की तरह भर्ती किया जाता है। यह क़दम अन्यायपूर्ण तथा ग़ैर-क़ानूनी है, इसे तुरंत बंद किया जाए।

20) फैक्ट्री के उत्पादन बढ़ने, निर्यात बढ़ने तथा गुणवत्ता बढ़ने की स्थिति में कई तरह की धनराशि, ख़रीदार कंपनी की तरफ़ से श्रमिक कल्याण के लिए दी जाती है जिसे मालिक अपने खाते में डाल लेते हैं। इस राशि को, 'वमानी मज़दूर संघर्ष समिति' की सहमति से, मज़दूरों में वितरित किया जाए जिससे वे और अच्छा काम करने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हों।

याद किये आज़ादी के दीवाने अशफाकुल्लाह खां

क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा

आज़ादी आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के जांबाज़ योद्धा अमर शहीद, ०अशफाकुल्लाह खां (22.10.1900-19.12.1928) को उनके 123 वें जन्म दिन पर, अदब-ओ-अहेतराम के साथ सलाम पेश करता है। उनके जीवन के कुछ रोचक तथ्य:-

- अशफाकुल्लाह खान को क्रांतिकारी आंदोलन से रूबरू कराने का श्रेय उनके बड़े भाई छोटाउल्लाह खान को जाता है जो अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल के साथ एक ही कक्षा में पढ़ते थे। 1918 में 'मैनपुरी षडयंत्र केस' के बाद से रामप्रसाद बिस्मिल फ़रार थे। छोटाउल्लाह खान ने भी बिस्मिल को कुछ दिन छुपने में मदद की थी। वे अपने छोटे भाई अशफाकुल्लाह खान को उनकी बहादुरी के किस्से सुनाया करते थे।

-अशफाकुल्लाह खान, यू पी के शाहजहांपुर ज़िले के रईस ज़मींदार पठान परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता शफ़ीक़ उल्लाह खान, शाहजहांपुर के शहर कोतवाल थे। इस लिए बिस्मिल उन्हें अपनी पार्टी 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन/ आर्मी' की सदस्यता नहीं देना चाहते थे। अशफ़ाक को अपने बर्ताव से यह सिद्ध करना पड़ा था कि इंक़लाबी ज़ज़्बे में वे किसी से भी कम नहीं पड़ेंगे, वे इस लायक़ हैं कि उन्हें पार्टी की सदस्यता दी जाए।

-अशफाकुल्लाह खान, संगठन के उन सदस्यों में थे जिन्होंने संगठन की मीटिंग में काकोरी ट्रेन डकैती की योजना का विरोध किया था। उनका तर्क था कि कई बेक़सूर मुसाफ़िर मारे जा सकते हैं लेकिन जब बहुमत से ये फैसला हुआ कि पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है और ट्रेन लूटी जाएगी तो उन्होंने आग्रहपूर्वक कहा कि वे इस मिशन में ज़रूर शामिल होंगे।

-अशफाकुल्लाह खां, सचिन्द्र बख्शी तथा राजेन्द्र लहड़ी एक साथ दूसरी श्रेणी के मुसाफिर डिब्बे में थे। उनकी ड्यूटी थी कि जैसे ही गाड़ी रुके वे बाहर कूदकर गार्ड को अपने क़ब्ज़े में ले लें। अशफ़ाक ने ही घोषणा की थी "यात्रियों डरो मत, हम आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी हैं, आपका जीवन पैसा और सामान सुरक्षित है। लेकिन ध्यान रहे कोई भी ट्रेन से भागेगा नहीं'।

-अशफ़ाक़ क़द काठी से मज़बूत थे। बक्से का ताला नहीं टूट रहा था तब बिस्मिल ने कहा 'अशफ़ाक के हाथ से ही टूटेगा ये'।

-अपनी फ़रारी के दौरान, अशफ़ाक़ नेपाल गए फिर कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। पलामू ज़िले के डाल्टनगंज में उन्होंने एक इंजीनियरिंग वर्कशॉप में 10 महीने नौकरी भी की।

- उनकी गिरफ़्तारी, 7 दिसंबर, 1926 को दिल्ली में उनके बचपन के एक दोस्त के घर से सुबह 11 बजे हुई। दोस्त ने ही ग़द्दारी की थी। उन्हें पहले फ़रीदाबाद जेल लाया गया था जहां से उन्हें फैज़ाबाद जेल ले जाया गया।

-19 दिसंबर 1928 को रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान तथा ठाकुर रोशन सिंह को एक ही दिन फांसी हुई थी। उनके एक और साथी राजेन्द्र लाहिड़ी को भी उसी दिन फांसी दीए जाने का अदालत का हुक्म हुआ था लेकिन उन्हें गोंडा जेल में तय वक़्त से दो दिन पहले 17 दिसंबर को ही लटका दिया गया था क्योंकि अंग्रेज़ों के ख़ुफ़िया विभाग को डर था कि क्रांतिकारी जेल पर धावा बोलकर उन्हें छुड़ा लेंगे।